



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 नवम्बर, 2008/27 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 4 मार्च, 2008

संख्या एस०जे०ई०-ए(३)११/२००५.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधीक्षक (गृह), वर्ग-II (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधीक्षक (गृह) वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू० एल० एफ०-ए(४)-७/९५, तारीख ०९-१२-१९९६ द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग, अधीक्षक (गृह) वर्ग-II, अराजपत्रित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, १९९६ का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध—क

**हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधीक्षक (गृह) वर्ग—III (अराजपत्रित)
पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम**

1. पद का नाम.—अधीक्षक (गृह)।
2. पदों की संख्या.—08 (आठ)।
3. वर्गीकरण.—वर्ग—II (अराजपत्रित)।
4. वेतनमान.—6400—200—7000—220—8100—275—10300—340—10640.
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन पद।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष के मध्य।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए गए हैं/किए गए थे।

(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/पदों को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—(क) अनिवार्य अर्हता.—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—लागू होगी।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—(1) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(2) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—सहायक अधीक्षक(गृह) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

पहला, दूसरा और तीसरा पद	सहायक अधीक्षक(गृह),
चौथा पद	सीधी भर्ती
रोस्टर प्रत्येक चौथे पद के पश्चात् दोहराया जाएगा।	

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों का जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरण पद पर गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपयुक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, जो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 क.—संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधीक्षक(गृह) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आना.—निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा(जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां संविदा के आधार पर नियुक्त अधीक्षक(गृह) को 9600/— रुपए की दर से समेकित संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200/— रुपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी निदेशक.—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त अधीक्षक(गृह) को 9600/— रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200/— रुपए वार्षिक की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं। होगी केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में अधीक्षक(गृह) के रूप में नियमितकरण/स्थायी आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

अधीक्षक (गृह) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संविदा की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अधीक्षक(गृह) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार अधीक्षक(गृह)के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् दिन को स्वयं मेव ही पर्यवसित(समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 9600/— रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

(Authoritative English Text of this department notification No. SJE-A(3)11/2005, dated 04-03-08 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th March, 2008

No. SJE-A(3)11/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superident (Home), Class-II(Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Superident(Home),Class-II-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 1997 (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Social & Women's Welfare Department, Superident, (Home)(Class-II-Non-Gazetted) Recruitment and Promotion rules, 1998 notified vide this Department notification No. WLF-A(4)-17/95 dated 09-1-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary.

ANNEXURE-‘A’

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT (HOME) (NON-GAZETTED) CLASS-II IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.**—Superintendent (Home)
- 2. Number of posts.**—8 (Eight)
- 3. Classification.**—Class-II (Non-Gazetted)
- 4. Scale of pay (be given in expanded notation).**— 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
- 5. Whether Selection or Non-Selection post.**—Selection.
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

- (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—
(a) **ESSENTIAL.**—Graduate of recognized University or its equivalent.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATIONS.**—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.—Age.—N.A.
Educational qualification—N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.

- (i) 75% by promotion
- (ii) 25% by direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Asstt. Supdt.

(Home) who possess 3 years regular services or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

The following roster shall be followed for filling up of posts :—

1st, 2nd, 3rd posts..... Asstt. Supdt.(Home)
4th post..... Direct Recruitment.

The roster will be repeated after every 4th posts.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—DPC to be presided over by time Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/others recruiting authority as the case may be.

15. A Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) CONCEPT.

(a) Under this policy, the Superintendent(Home) the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **Post Falls Within The Purview of HPPSC.**—The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e.H.P.P.S.C.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(II) Contractual Emoluments.—The Superintendent (Home) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 9600/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). As annual increase Rs.200/- in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPPSC.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the competent authority from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 9600/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 200/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as seniority/scale etc. shall be.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only Maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract.

Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporally unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as Superintendent(Home) in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—N.A.

18. Powers to Relax.— Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the _____ & the Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this-----day of -----in the year.....BetweenSh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o.....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Impowerment Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY). The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a wardens on contract basis on the following terms & conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a warden on contract basis for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on..... and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be paid Rs 9600/-per month. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.
5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for salary for the period of absence from duty.
7. Transfer of the appointee on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer at the minimum of pay scale.
10. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee(s) as well as EPF/GPF.

WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

2.

 (Name and Full Address)

(Signature of the First party)

1.

.....

(Name and Full Address)

2.

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

शिमला-2, 13 सितम्बर, 2007

संख्या एस.जे.ई.-ए (3)17/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श, से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सांख्यिकी सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी.डी.(ए)4-3/80, तारीख 9-9-81 द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जन जाति विभाग सांख्यिकी सहायक (वर्ग—III (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1981 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

उपाबन्ध—क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में रूपए 800—9200 के वेतनमान में
सांख्यिकी सहायक वर्ग III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम : सांख्यिकी सहायक ।

2. पदों की संख्या : 11(ग्यारह) ।

3. वर्गीकरण : वर्ग—III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान : 5800—200—7000—220—8100—275—9200 ।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद:** अचयन पद।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु :** 18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थी के लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे, किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.—(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—**
अनिवार्य अर्हता:— कला स्नातक/विज्ञान स्नातक गणित/अर्थशास्त्र को अधिमानता। **वांछनीय अर्हताएं :** (i) सांख्यिकी डाटा एकत्रित एवं संकलित करने के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों/रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु :** लागू नहीं, **शैक्षणिक अर्हता:** लागू नहीं

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमेंट आधार पर।

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—कम्प्यूटर पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को शामिल करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समकक्ष वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सेकेन्डमेंट आधार पर।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लाने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन (नया उपबन्ध).—(I) संकल्पना: (क) इस पॉलिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश में सांख्यिकी सहायक की संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जाब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेहन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक को 8700/— रूपए (जो वेतनमान के आरम्भिक आरम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200/— रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी : निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदा पर नियुक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार : अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII)

(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8700/— रूपए (जो वेतनमान के आरम्भिक आरम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) की दर से नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200/— रूपए वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य, आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ.) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञेय नहीं होगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में सांख्यिकी सहायक के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

सांख्यिकी सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मध्यम से आज तारीख..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सांख्यिकी सहायक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सांख्यिकी सहायक के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. **प्रथम पक्षकार** का संविदा वेतन 8700/- रूपए प्रतिमास होगा।
3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पद नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A(3)17/2005, dated -----
-----as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]

Shimla-2 the 13-9-2007

No. SJE-A(3)17/2005.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Statistical Assistant, Class-III(Non-Gazetted)in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department,Statistical Assistant,Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings. —(1) The Tribal Development Department,Statistical Assistant, (Class-III Non-Gazetted)Recruitment and Promotion rules, 1981 notified vide this Department notification No. T.D.(A)4-3/80. dated 9.9.81 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary(SJ&E).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STATISTICAL ASSISTANT (CLASS-III NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post: STATISTICAL ASSISTANT
2. Number of posts : 11 (Eleven)
3. Classification : Class-III (NON-GAZETTED)
4. Scale of pay (be given in expanded notation) : 5800-200-7000-220-8100-275-9200
5. Whether Selection or Non-Selection post: Non Selection
6. Age for direct recruitment : Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—
(a) ESSENTIAL: B.A/B/Sc preferably with Maths/Economics.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—(i) Two years experience in the field of collection/compilation of statistical data.

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.*—**Age:**-----**No. Educational qualification---** No.

9. *Period of probation, if any.*—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing .

10. *Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.*—50% Percent by promotion failing which by secondment basis. 50% by Direct recruitment or on contract basis.

11. *In case of recruitment by promotions, secondment, transfer grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.*—By promotion from amongst the incumbents of Computers having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from other Departments of H.P. Government.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that:

(i) In all case where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitment's of the preceding proviso, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account

towards the length of service if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition—*As may be constituted by the Government from time to time.

13. *Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment—*As required under the law.

14. *Essential requirement for direct recruitment.*—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15.A *Selection for appointment to the post by contract appointment.*— (i)CONCEPT.

(a) Under this policy, the Statistical Assistant in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **Post Falls Within The Purview of HPPSC.**—The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(ii) Contractual Emoluments.—The Statistical Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 8700/- P.M. An amount of Rs 200/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(iv) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSB.

(v) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.B. from time to time.

(vi) **AGREEMENT** : After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(vii) **TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.8700/- per month. The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 200/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporally unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(viii) **RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.**—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption as Statistical Assistant in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Statistical Assistant_____ & the Government of Himachal Pradesh through Director Social Justice & Empowerment Department.

This agreement is made on this-----day of -----in the year.....Between

Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o.....

.....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Empowerment Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ..Statistical Assistant..... on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Statistical Assistant.....for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.
2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs 8700/- P.M.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.
5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of the appointee.....on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contractual..appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer at the minimum of pay scale.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2.

.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2.

.....

.....

(Name and Full Address)

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 24 अक्टूबर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)ई(2) 90/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सेर बनेडा, तहसील सोलन, जिला सोलन में सोलन-जौणाजी-दर्जा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, द0 क्षेत्र शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघे-विस्वा) में
सोलन	सोलन	सेर बनेडा	774 / 682 / 36 / 4	0-5
			774 / 682 / 36 / 3	0-1
			कुल किता-2	0-6

शिमला-2, 7 नवम्बर, 2008

सं० पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5)300/2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रांरग तहसील मूरंग, जिला

किन्नौर में खारों रिब्बा अकपा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (है0) में
किन्नौर	मूरंग	सरंग खास	1051 / 1	0-02-80
			1053 / 1	0-02-54
			1056 / 1	0-00-94
			1057 / 1	0-00-08
			कुल किता 4	0-06-36

शिमला-2, 7 नवम्बर, 2008

स0 पी0बी0डब्ल्यू (बी0)एफ(5)301 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव पारंग तहसील मूरंग, जिला किन्नौर में खारों रिब्बा अकपा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (है0) में
किन्नौर	मूरंग	पारंगा खास	212 / 1	0-17-79
			कुल किता 1	0-17-79

सं पी0बी0डब्ल्यू (बी0)एफ(5)302/2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव स्कीवा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर में खारों रिब्बा अकपा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (है0) में
किन्नौर	मूरंग	स्कीवा	134 / 1	0-03-31
			135 / 1	0-00-16
			136	0-00-21
			846 / 146	0-01-26
			145 / 1	0-03-28
			222 / 1	0-09-10
			220 / 1	0-01-37
			211	0-00-05
			212	0-00-04
			213	0-00-04
			214	0-00-18
			740 / 1	0-04-95
			745 / 1	0-01-75
			745 / 2	0-01-04
			630 / 1	0-01-23
			630 / 2	0-01-10
			631	0-01-17
			632	0-00-32
			764 / 1	0-03-27
			731 / 1	0-00-84
			730 / 1	0-00-24
			729 / 1	0-03-70
			728 / 1	0-06-40
			727	0-01-00
			733	0-00-74
			734	0-00-74
			737	0-02-74
			878 / 774 / 1	0-02-59
			876 / 774	0-00-56
			877 / 774 / 1	0-00-39
			726 / 1	0-03-65
			790	0-02-50
			कुल किता 32	0-59-92

शिमला-2, 14 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)187 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुफरी, तहसील शिमला, जिला शिमला में कुफरी बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, द0 क्षेत्र शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघे-विस्वा) में
शिमला	शिमला	कुफरी कोटी	345 / 2	0-04-32
			355	0-00-72
			360 / 2	0-02-26
			352	0-01-20
			353	0-00-35
			354	0-00-55
			कुल किता-6	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव।

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 नवम्बर, 2008

संख्या एच.पी.ई.आर.सी / 416.—विद्युत, अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 127 के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (य ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त् करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के, 24 मार्च, 2005 के अंक में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अपील प्राधिकारी को

अपील करने की प्रक्रिया) विनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम, पूर्व प्रकाशन पश्चात्, बनाता है :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(अपील प्राधिकारी को अपील करने की प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 है।
(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **विनियम 3 में संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अपील प्राधिकारी को अपील करने की प्रक्रिया) विनियम, 2005 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में आए शब्द “एक-तिहाई” के स्थान पर शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए।

आयोग के आदेश द्वारा,
हस्ता/—
सचिव।

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th November, 2008

No. HPERC/416.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers conferred by section 127 read with Clause (zo) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 24th March, 2005.

REGULATIONS

1. *Short title and commencement.*— (1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) (first Amendment) Regulations, 2008.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Regulation 3.*—In sub-regulation (2) of regulation 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure for Filing Appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005, for the words, “one third” for the word “half” shall be substituted.

By the order of the Commission,
-Sd-
Secretary.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2008.

संख्या रैव-बी0ए0(3)-5/2000.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्या: 10-5/73-रैव-ए, तारीख 3-10-1975 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 4-10-1975 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफॉर्मज रुल्ज़, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 123 में यथा अपेक्षित के अनुसार एतद् द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है;

यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति प्रस्तावित संशोधन की बाबत कोई आक्षेप/सुझाव करना/देना चाहता है, तो वह उसे (उन्हें) वित्तायुक्त एवं सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को, इन नियमों के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई है/हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

संक्षिप्त नाम	1.	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफॉर्मज (संशोधन) नियम, 2008 है।
नियम 38-A का संशोधन	2.	<p>हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफॉर्मज नियम, 1975 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 38-A में,—</p> <p>(a) उप नियम (1) के पश्चात विद्यमान चिन्ह “;” का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>“for the purposes other than setting up of industrial units. For the purpose of setting up industrial units, application shall be made to the Director Industries in Form LR-XIV-A”;;</p> <p>(b) उप नियम (2) खण्ड (a) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (aa) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>“(aa) On receipt of application, complete in all respects under sub-rule (1), the Director Industries shall recommend the application within a period of 7 days from the date of its receipt by him to the State Government for its consideration;;”</p> <p>(c) उप नियम (2) के खण्ड (b) में, शब्द, कोष्टक और</p>

		<p>अक्षर "Clause (a)", के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अक्षर "or by the Director of Industries under clause (aa)" अन्तःस्थापित किए जाएंगे;</p> <p>(d) उप नियम (3) में,—</p> <p>(i) खण्ड (c) के सामने उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>"for construction such area as of commercial may be certified establishments by the Collector like shops, petrol of the District pumps, automobiles concerned. "; service station, godown, showroom etc.</p> <p>(ii) खण्ड (j) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>"(k) for establishment such area as may be of educational institution. certified by the department of Education/Technical education/ Health education, as the case may be."</p> <p>(e) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम (4) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>"(4.) (a) For the purpose of setting up of Industries, a non agriculturist who has obtained approval of the State Government under clause (b) of sub-rule (2), shall apply in Form LR-XIV-B, duly supported by the documents specified in Part-II of Form LR-XIV, to the Sub-Divisional Officer (Civil) within whose jurisdiction the land is situated.</p> <p>(b) On receipt of application, complete in all respects under sub-rule 4 (a), the Sub-Divisional Officer(Civil), on verification of the necessary documents and title of land in question, shall pass an order for carrying out registration of sale deed and such order shall mention the ownership, title of land, Khasra number, revenue estate and total area of land, which shall not exceed the quantum of land for</p>
--	--	--

		which permission of State Government has been accorded under sub-rule (2) (b)."
फार्म LR-XIV के पार्ट-11 का संशोधन।	3.	<p>फार्म LR-XIV के पार्ट-11 में,</p> <p>(क) नद संख्या (IV) के पश्चात् निम्नलिखित नद अन्तःस्थापित क जाएगी अर्थात्:-</p> <p>"(IV-A). Balance land certificate of seller(s) issued by Tehsildar of the area concerned."</p> <p>(ख) नद (IX) की उप नद (d) में, "Public utility" शब्दों के पश्चात् "/ for construction of commercial establishments like shops, petrol pumps, automobiles service station, godown, showroom etc." चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।</p> <p>(ग) नद (IX) की उप नद (d) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-</p> <p>"(e) Essentiality certificate from department of Housing and the concerned Deputy Commissioner, independently, in case of construction of Apartment as defined in the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005 (Act No. 21 of 2005).</p> <p>(f) Essentiality certificate from department of Bio-technology of the State Government and the concerned Deputy Commissioner, independently, in case of setting up of Biotechnology unit.</p> <p>(g) Essentiality certificate from department of Information Technology of the State Government and the concerned Deputy Commissioner, independently, in case of setting up of information technology unit.</p> <p>(h) Essentiality certificate from department of Education/Technical education/Health education, as the case may be, for establishment of educational institution."</p>
फार्म LR-XIV-A और LR-XIV-B का जोड़ा जाना।	4.	<p>उक्त नियमों में फार्म LR-XIV के पश्चात् निम्नलिखित फार्म LR-XIV-A और LR-XIV-B जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-</p> <p style="text-align: center;">" FORM LR-XIV-A" (See Sub-rule (1) of rule 38-A) APPLICATION FOR PERMISSION REQUIRED UNDER SUB RULE (1) OF RULE 38-A OF THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS RULES, 1975 FOR SETTING UP OF INDUSTRIAL PROJECTS. (to be submitted to Director, Industries, H.P.)</p>

	<p>1. Name of the applicant/Company_____</p> <p>2. Permanent address Village/Town_____Tehsil_____ District_____State_____</p> <p>3. Present occupation and address _____ _____</p> <p>4. Purpose for which the land is required _____</p> <p>5. Particulars of the land applied for: i) District. ii) Sub-Division. iii) Tehsil. iv) Revenue Estate(s).</p> <p>6. Whether the applicant applied previously for such permission if so, give the following particulars:- (a) Date of application, if known. (b) Whether permission granted or refused (the date of order the State Government.) (c) Particulars of land permitted to be transferred previously:- i) District. ii) Sub-Division. iii) Tehsil. iv) Name of Estate with Hadbast number. v) Khasra number with area and classification.</p> <p>7. Details of Essentiality Certificate with copy thereof.</p> <p>8. Details of Single Window Authority approval with copy thereof.</p> <p>9. Details of Provisional Registration with copy thereof if not covered under item 8 above.</p> <p>10. Any other information which the applicant consider to be relevant.</p> <p>I solemnly affirm and declare that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed therein.</p> <p style="text-align: right;">Signature of the Applicant. Address</p> <p>Dated: _____</p> <p style="text-align: center;">-----For use of Director Industries-----</p> <p>Remarks of the Director, Industries H.P.</p> <p style="text-align: center;">“FORM LR-XIV-B” (See Sub-rule (4) of rule 38-A) APPLICATION FOR PERMISSION REQUIRED UNDER SUB RULE (1) OF RULE 38-A OF THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS RULES, 1975 FOR SETTING</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">UP OF INDUSTRIAL PROJECTS. (to be submitted to Sub-Divisional Officer (Civil) concerned alongwith documents specified in Part-II of Form LR-XIV)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>1. Name of the applicant/Company _____ resident of village _____ Tehsil _____ District _____</p> <p>2. Permanent address Village/Town _____ Tehsil _____ District _____ State _____</p> <p>3. Present occupation and address _____ _____</p> <p>4. Purpose for which the land is required _____</p> <p>5. Particulars of the land applied for: i) District. ii) Tehsil. iii) Number of estate (Hadbast) with name of Estate. iv) Khata/Khatoni/Khasra Numbers alongwith total No. of Kitas with area and classification of land.</p> <p>6. Particulars of the land holder from whom land is intended to be transferred Name _____ son/daughter/wife of _____ resident of village _____ Tehsil _____ District _____</p> <p>7. Particulars of approval of State Government under section 118(h): 1. Letter number and date of approval of State Government alongwith copy thereof. 2. Total area permitted for purchase by State Government. 3. Name of Revenue Estate(s) in which permission for purchase of land granted by State Government.</p> <p>8. Any other information which the applicant consider to be relevant. I solemnly affirm and declare that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed therein.</p> <p style="text-align: right;">Signature of the Applicant. Address"</p>
--	--

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व) ।

[Authoritative English Text of Government Notification No.Rev.B.A.(3)-5/2000, dated 15.11.2008 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th November,2008.

No.Rev.B.A.(3)-5/2000.—In exercise of the power conferred by section 122 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 (Act No.8 of 1974), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules,1975 notified vide Government Notification No.10-5/73-Rev.A, dated 3.10.1975 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 4.10.1975 and the same are hereby published for the information of general public as required under section 123 of the Act *ibid*;

If any interested person has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed amendment, he may send the same to the Financial Commissioner-cum-Secretary(Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of these rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objection(s) /suggestion(s) if any, received within the period specified above shall be duly considered by the Government before finalising these rules, namely:-

DRAFT RULES

Short title	1.	These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules,2008.
Amendment of rule 38-A.	2.	<p>In rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules,1975 (hereinafter referred to as the 'said rules');</p> <p>(i) the sign “,” existing after sub-rule (1) shall be deleted and thereafter the following shall be added, namely:- “for the purposes other than setting up of industrial units. For the purpose of setting up industrial units, application shall be made to the Director Industries in Form LR-XIV-A”,”;</p> <p>(j) after clause (a) of sub-rule (2) the following clause (aa) shall be inserted, namely;- “(aa) On receipt of application, complete in all respects under sub-rule (1), the Director Industries shall recommend the application within a period of 7 days from the date of its receipt by him to the State Government for its consideration;”;</p> <p>(k) in clause (b) of sub-rule (2) after the word, brackets and letter “clause (a)”, the words, brackets and letters “or by the Director of Industries under clause (aa)” shall be inserted;</p> <p>(l) in sub-rule (3),-</p> <p>(i) for the provisions against clause (c), the</p>

		<p>following shall be substituted, namely:-</p> <p>“for construction such area as of commercial may be certified establishments by the Collector like shops, petrol of the District pumps, automobiles concerned.”;</p> <p>service station, godown, showroom etc.</p> <p>(ii) after clause (j) the following clause shall be added, namely:-</p> <p>“(k) for establishment such area as may of educational be certified by the institution. Department of Education/Technical education/ Health education, as the case may be.”.</p> <p>(m) After sub-rule (3), the following sub-rule (4) shall be added, namely:-</p> <p>“(4.) (a) For the purpose of setting up of Industries, a non agriculturist who has obtained approval of the State Government under clause (b) of sub-rule (2), shall apply in Form LR-XIV-B, duly supported by the documents specified in Part-II of Form LR-XIV, to the Sub-Divisional Officer (Civil) within whose jurisdiction the land is situated.</p> <p>(b) On receipt of application, complete in all respects under sub-rule 4 (a), the Sub-Divisional Officer(Civil), on verification of the necessary documents and title of land in question, shall pass an order for carrying out registration of sale deed and such order shall mention the ownership, title of land, Khasra number, revenue estate and total area of land, which shall not exceed the quantum of land for which permission of State Government has been accorded under sub-rule (2) (b).”</p>
Amendment of Part-II of Form LR-XIV.	3.	<p>In Part-II of Form LR-XIV,</p> <p>(a) after item No.(IV) the following Item shall be inserted, namely:-</p> <p>“(IV-A). Balance land certificate of seller(s) issued by Tehsildar of the area concerned.”.</p> <p>(b) in sub-item (d) of item (IX) after the words, “Public utility”, the sign and word “/for construction of commercial establishments</p>

		<p>like shops, petrol pumps, automobiles service station, godown, showroom etc." shall be inserted.</p> <p>(c) after sub-item (d) of item (IX) following sub-items shall be added, namely:-</p> <p>“(e) Essentiality certificate from department of Housing and the concerned Deputy Commissioner, independently, in case of construction of Apartment as defined in the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005 (Act No. 21 of 2005).</p> <p>(f) Essentiality certificate from department of Bio-technology of the State Government and the concerned Deputy Commissioner, independently, in case of setting up of Biotechnology unit.</p> <p>(g) Essentiality certificate from department of Information Technology of the State Government and the concerned Deputy Commissioner, independently, in case of setting up of information technology unit.</p> <p>(h) Essentiality certificate from department of Education/Technical education/Health education, as the case may be, for establishment of educational institution.””</p>
Addition of Forms LR-XIV-A and LR-XIV-B.	4.	<p>In the said rules after Form LR-XIV, the following Forms LR-XIV-A and LR-XIV-B shall be added, namely:-</p> <p>“FORM LR-XIV-A”</p> <p>(See Sub-rule (1) of rule 38-A)</p> <p>APPLICATION FOR PERMISSION REQUIRED UNDER SUB RULE (1) OF RULE 38-A OF THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS RULES, 1975 FOR SETTING UP OF INDUSTRIAL PROJECTS.</p> <p>(to be submitted to Director, Industries, H.P.)</p> <p>.....</p> <p>1. Name of the applicant/Company_____</p> <p>2. Permanent address Village/Town_____Tehsil_____ District_____ State_____.</p> <p>3. Present occupation and address _____</p> <p>4. Purpose for which the land is required _____</p> <p>5. Particulars of the land applied for:</p> <p>i) District.</p> <p>iii) Sub-Division.</p> <p>ii) Tehsil.</p> <p>iii) Revenue Estate(s).</p>

	<p>6. Whether the applicant applied previously for such permission if so, give the following particulars:-</p> <p>(a) Date of application, if known.</p> <p>(b) Whether permission granted or refused (the date of order the State Government.)</p> <p>(c) Particulars of land permitted to be transferred previously:-</p> <p>i) District.</p> <p>ii) Sub-Division.</p> <p>iii) Tehsil.</p> <p>iv) Name of Estate with Hadbast number.</p> <p>v) Khasra number with area and classification.</p> <p>7. Details of Essentiality Certificate with copy thereof.</p> <p>8. Details of Single Window Authority approval with copy thereof.</p> <p>9. Details of Provisional Registration with copy thereof if not covered under item 8 above.</p> <p>10. Any other information which the applicant consider to be relevant.</p> <p>I solemnly affirm and declare that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed therein.</p> <p style="text-align: right;">Signature of the Applicant.</p> <p style="text-align: right;">Address</p> <p>Dated: _____</p> <p style="text-align: center;">-----For use of Director Industries-----</p> <p>Remarks of the Director, Industries H.P.</p> <p style="text-align: center;">“FORM LR-XIV-B”</p> <p style="text-align: center;">(See Sub-rule (4) of rule 38-A)</p> <p style="text-align: center;">APPLICATION FOR PERMISSION REQUIRED UNDER SUB RULE (1) OF RULE 38-A OF THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS RULES, 1975 FOR SETTING UP OF INDUSTRIAL PROJECTS.</p> <p style="text-align: center;">(to be submitted to Sub-Divisional Officer (Civil) concerned alongwith documents specified in Part-II of Form LR-XIV)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>1. Name of the applicant/Company_____</p> <p>resident of village_____</p> <p>Tehsil_____ District_____</p> <p>2. Permanent address</p> <p>Village/Town _____ Tehsil_____</p> <p>District_____ State_____</p> <p>3. Present occupation and address_____</p>
--	--

		<p>_____.</p> <p>4. Purpose for which the land is required _____.</p> <p>5. Particulars of the land applied for:</p> <p style="padding-left: 40px;">i) District.</p> <p style="padding-left: 40px;">ii) Tehsil.</p> <p style="padding-left: 40px;">iii) Number of estate (Hadbast) with name of Estate.</p> <p style="padding-left: 40px;">iv) Khata/Khatoni/Khasra Numbers alongwith total No. of Kitas with area and classification of land.</p> <p>6. Particulars of the land holder from whom land is intended to be transferred</p> <p style="padding-left: 40px;">Name_____son/daughter/wife</p> <p style="padding-left: 40px;">of_____resident of village _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Tehsil_____District_____.</p> <p>7. Particulars of approval of State Government under section 118(h):</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Letter number and date of approval of State Government alongwith copy thereof.</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Total area permitted for purchase by State Government.</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Name of Revenue Estate(s) in which permission for purchase of land granted by State Government.</p> <p>8. Any other information which the applicant consider to be relevant.</p> <p style="padding-left: 40px;">I solemnly affirm and declare that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed therein.</p> <p style="text-align: right;">Signature of the Applicant.</p> <p style="text-align: right;">Address”</p>
--	--	--

By Order,
Sd/-
F.C.-cum-Secretary (Revenue).

ब अदालत श्री Balbir Singh Lagwal, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

Nyima Delma w/o Shri Lobsang Sherep, r/o Tashijgang, P. O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Nyima Delma w/o Shri Lobsang Sherep, r/o Tashijgang, P. O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Pema Lhamo का जन्म

दिनांक 25-11-1990 को मुहाल Tashijang में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-12-2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 16-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

BALBIR SINGH LAGWAL,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री वी0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)

केस नम्बर :

तारीख पेशी : 15-12-2008

रविन्द्र कुमार

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी मुहाल अरला, मौजा अरला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के समायल का जन्म दिनांक 31-7-2000 को हुआ है। मगर ग्राम पंचायत अरला के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर का एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2008 को सुबह 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा समायल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार की जन्म तिथि 31-7-2000 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-10-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विचित्र सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नम्बर :

तारीख पेशी : 15-12-2008

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी अप्पर मैझा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी अप्पर मैझा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री सलोनी का जन्म दिनांक 26-4-2003 को ग्राम पंचायत मैझा में हुआ है मगर ग्राम पंचायत मैझा के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर का एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2008 को सुबह 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा सलोनी के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-10-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

विचित्र सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अच्छर सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 09/2008

तारीख पेशी : 22-12-2008

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इशतहार मुस्त्री मुनादी बराये तल्वी आम जनता।

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र पेश किया है व निवेदन किया है कि उसने रेनुका पुत्री श्री रमेश चन्द डोगरा, निवासी फस्टा, डाकघर डरोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा से हिन्दु रीति-रिवाज के साथ शादी अपने निवास स्थान गांव भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल में दिनांक 1-10-2002 को करवाई थी। परन्तु अपनी शादी ग्राम पंचायत अभिलेख भ्रान्ता में दर्ज न करवाई थी। इस सम्बन्ध में रेनुका पुत्री श्री रमेश चन्द ने भी अपना शपथ-पत्र दिया है, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि उसने श्री अनिल कुमार पुत्र श्री आत्मा राम से हिन्दू रीति-रिवाज से शादी दिनांक 1-10-2002 को की है। प्रार्थी द्वारा अपनी शादी पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर नहीं सुना जावेगा व आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

ये इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 3-11-2008 को जारी हुआ।

मोहर।

अच्छर सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अच्छर सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/2008

तारीख पेशी : 22-12-2008

श्री अरुण कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इशतहार मुस्त्री मुनादी बराये तल्वी आम जनता।

श्री अरुण कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र पेश किया है व निवेदन किया कि उसने अंजू सिंह पुत्री श्री प्रताप सिंह, निवासी व तहसील झांसी, जिला झांसी (U. P.) से हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शादी अपने निवास स्थान गांव भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल में दिनांक 27-1-2008 को करवाई थी। परन्तु अपनी शादी ग्राम पंचायत अभिलेख भ्रान्ता में दर्ज न करवाई थी। इस सम्बन्ध में अंजू सिंह पुत्री श्री प्रताप सिंह ने भी अपना शपथ-पत्र दिया है, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि उसने श्री अरुण कुमार पुत्र श्री आत्मा राम से हिन्दू रीति-रिवाज से शादी दिनांक 27-1-2008 को की है। प्रार्थी द्वारा अपनी शादी पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर नहीं सुना जावेगा व आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

ये इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 3-11-2008 को जारी हुआ।

मोहर।

अच्छर सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अच्छर सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11/2008

तारीख पेशी : 22-12-2008

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इश्तहार मुस्त्री मुनादी बराये तल्वी आम जनता।

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र पेश किया है व निवेदन किया कि उसने नीतू पुत्री श्री अमर नाथ, निवासी H. No. 421/9 Mohalla Quadri, Gurdaspur, Punjab से हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शादी अपने निवास स्थान गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल में दिनांक 26-9-2006 को करवाई थी। परन्तु अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत भ्रान्ता के अभिलेख में न करवाया है। इस सम्बन्ध में श्रीमती दर्शना रानी विधवा श्री अमर नाथ माता नीतू ने व नीतू पुत्री श्री अमर नाथ ने भी शपथ-पत्र पेश किया है। जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि उसकी पुत्री नीतू की शादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द निवासी भ्रान्ता, उप-तहसील थुरल से हिन्दू रीति-रिवाज से शादी दिनांक 26-9-2006 को की है। प्रार्थी द्वारा अपनी शादी पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर नहीं सुना जावेगा व आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 3-11-2008 को जारी हुआ।

मोहर।

अच्छर सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 5/2008.

श्री प्रकाश धीमान पुत्र श्री टीडू राम, वासी मूहीं, मौजा गरली, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह आम व खास को बजरिया नोटिस हजा इत्तलाह की जाती है कि श्री प्रकाश धीमान पुत्र श्री टीडू राम, निवासी मुहाल मूहीं, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा अपनी माता श्रीमती केसरी देवी की मृत्यु तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा

अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय क्रमांक: HFW-H-KGR (B&D)-288, dated 30-6-2008 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। सायल के अनुसार श्रीमती केसरी देवी की मृत्यु तिथि 29-2-2004 है और उसकी मृत्यु गांव मूहीं, ग्राम पंचायत मूहीं, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा में हुई है।

अगर किसी शख्स को उपरोक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मूहीं में दर्ज कराने बारे कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 4-12-2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपना उजर पेश कर सकता है। ऐसा न करने की सूरत में मजीद कार्यवाही हस्व जाबता अमल में लाई जायेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी बदेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी बदेहड़, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री अनामिका का नाम ग्राम पंचायत बदेहड़ में गलती से दर्ज नहीं करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जाये। उसकी पुत्री का नाम अनामिका है। जन्म तिथि 29-2-2004 तथा बच्चे का जन्म स्थान होस्पिटल चौन्तड़ा है।

अतः इस इशतहार से समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-11-2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

अशोक चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अशोक चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री राम लाल पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी बैला, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व विभाग।

श्री राम लाल पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी बैला, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम चन्द्रमणी है परन्तु कागजात माल भडयाडा बुहला में उसका नाम गलत धुधर दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपने स्कूल प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, परिवार रजिस्ट्रर नकल व जमाबन्दी संलग्न प्रस्तुत कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

अशोक चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।